207 Calling Attention [RAJYA SABHA] to severe drought

MR. DEPUTY CHAIRMAN: II the Chairman has written, I have not seen it. If he has allowed you, that is a different matter. But The Chairman has not allowed you. So, please do not raise it.

श्वी शिव चन्द्र झाः उसमें कहा है कि स्पेशल मेंशन की तरह उठाइये ग्राप, उसमें यह लिखा हग्रा है ।

श्री उपसभापति : इसमें दिया हुम्रा है जो स्पेशल मेंशन दीजिए, तो विचार करेंगे । श्री शिव चन्द्र झा : ग्रच्छा, दूसरो बात । श्री उपसभापति : ग्रब एक बात हो गई ।

श्री शिव चन्द्र झा ः दूसरी वात सुन लीजिए । म्रखवार में ग्राज ग्रापने देखा होगा (व्यवधान)

श्री उपसभापति : वह सब प्वाइंट ग्राफ ग्राईर नहीं है।

श्री शिव चन्द्र झा : नहीं गम्भीर विषय हे ... (व्यवधान)

श्री उपसलापति : सारे विषय गम्भीर होते हैं, लेकिन जिसकी इजाजत होती है बह सब से ज्यादा गम्भीर होता है।

भी सिन चन्द्र सा : यच्छा फिर SHRI HAREKRUSHNA MALLICK (Orissa): Sir, how can it be 'theersri' when he has not mentioned first two?

श्री उपसभापति : ग्राज बहुत बिजी प्रोग्राम है, झा जी, जरा हाउस को चलने दीजिए ।

श्री शिव चन्द्र झा : क्या सदन जान सकता है कि सेशन बढ़ेगा कि नहीं ताकि इमको उसी हिसाब से कार्यक्रम बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत से बिजनेस बाकी हैं ।

श्री उपसभापति : ग्राप इसकी चिन्ता न करिए । बढ़ेगा तो इत्तिला दी जाएगी । जब तक इत्तिला नहीं है, तो इसका मतलब है कि नही बढ़ेगा ।

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, ब्रिटिश कामन्स सभा में ...

in various parts 208 of *the Country*

श्री उपसभापति : वह खत्म हो गया। कोई पोइन्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं उठता। काहे को ग्राप टाइम बर्बाद करते हैं।

श्वी रामेश्वर सिंह : आप थोड़ी हमारी मदद कर दीजिए ।

श्री उपसभापति : ग्राप मेरी मदद कीजिए । मैं इसप की बात समझ गया(क्यबधान) ग्राव ग्राप बैठिए ।

श्री रामेश्वर सिंह ः क्या ग्राप विदेश मंत्री को नहीं चाहते कि इस सदन में या कर जानकारी बतायें । ग्राज ग्रखवार में कृष्ण है कि पोस्तपोन हो गया MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let not what

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let not what Mr. Rameshwar Singh says be recorded. SHRI RAMESHWAR SINGH: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let us now take up the Calling Attention Motion. Yes, Mr. Krishna Mohan Bhamidipati.

ALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Severe drought in various parts of the Country

• SHRI KRISHNA MOHAN BHAMIDIPATI (Andhra Pradesh): Sir, I beg to call the attention of the Minister of Agriculture to the severe drought prevailing in various parts of the country and the steps taken toy the Government to meet the situation.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHD. KHAN): Sir, Hon'ble Members will recall that in the statement made by my senior colleague in the House on 12th October, 1982, in response to a Calling Attention Motion by Shri Kalyan Roy and other Hon'ble Members, he had informed the House aboubt the drought situation obtaining at that time. Subsequently, further information was received from the States

*Not recorded.

and altogether a record level ceilings of expenditure upto Rs. 436.26 crores were sanctioned to 15 States and one Union Territory. 1.13 lakh tonne of foodgrains have also been allotted to the States by way of special drought relief to be utilised for payment of part w ages to labour in kind at the rate of 1 kg. of foodgrains per manday. Funds have also been sanctioned under the head 'Gratuitous Relief and Nutritional Programme' for old, infirm and the indigent as well as for pre-school going children and expectant and lac-tating mothers. Out of the ceilings sanctioned during last year_i Rs. 209.77 crores were earmarked for employment generation.

The ceilings of assistance sanctioned last year also had a component valid for the current year. This was so in the case of Gujarat, Kerala, Maharashtra, Orissa and Rajasthan. For Tamil Nadu and Karnataka ceilings of expenditure were sanctioned last month but cover both the years.

Fresh memoranda have been received from the States of Bihar, Kerala, Andhra Pradesh and Madhva Pradesh for the second time and in the case of Orissa and West Bengal for the third time. Central teams have already visited the States of Kerala, Bihar, West Bengal and Madhya Pradesh. Bihar have been sanctioned an additional assistance of Rs. 8.53 crores during the current year. Reports of the Central Team, from Kerala, Madhya Pradesh and Bihar are under processing. A Central team has already left for Andhra Pradesh yesterday and another shall be visiting Rajasthan in the near future. Pending the visit of the Central Team to Rajasthan a sum of Rs. 11 crores has been sanctioned on ad-hoc basis to continue the relief operations. A supplementary memorandum was also received from Pondicherry for the second time and a ceiling of Rs. 44 lakhs has been sanctioned to undertake relief measures in the Union Territory. In view of the earlier sanction released to Orissa for use

in various parts 210 of *the Country*

during the current year, it has been decided not to depute a Central Team to the State.

Providing relief to the people In drought affected areas is a continuing exercise and requests of States for assistance during the current year are also under $activ_e$ consideration. Sanctions to the extent of Rs. 117.82 crores have already been issued to 8 States during the current year. As the new financial year has just begun, the entire margin money as well as budgetary provisions under different sectors are available to the States for continuing the relief measures. Central assistance to supplement their efforts in this behalf would be sanctioned as soon as the cases are finalised.

Drought management with special focus on drinking water problem was reviewed by Ministry of Agriculture with the affected States and it gives me pleasure in informing the House that all the States including Tamil Nadu and Kerala are confident of meeting the challenge posed by the drinking water problem in this hot season. A draft 'Action Plan' has been sent to the States, reiterating Prime Minister's 12-Point Programme on Drought Management. States have also been requested to make available 2-3 guintals of foodgrain at each Panchayat level, as an antistarvation measure. The need for taking measures regarding public health and cattle conservation were also discussed.

The Railway have issued instructions for transportation of fodder on concesional freight to the drought affected States. The Hon'ble Members must be aware of the efforts being made by the Railways to augment the water supply in Madras city bj transporting' water from Andhra Pradesh. Our Prime Minister visited Tamil Nadu on 28th March and saw some relief works in the interior of North Arcot district. She also **wenl** round the Madras city and was appraised of the drinking water problem.

211 *Calling Attention* to *severe drought* [Shri Arif Mohd. Khan]

States hav_e been advised to enforce strict monitoring and to keep the Central Government informed about the utilisation of the Central assistance and the foodgrain allotment. They have been particularly advised to monitor the drinking water situation, cattl_e conservation, employment generation and nutritional status of the vulnerable groups at village level.

[RAJYA SABHA]

I wish to assure the House that Government ar_e fully seized of **the** situation and will extend all possible assistance to the States in thi_s hour of distress.

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है इसी पर मैं जानता हूं कि आप गांव से आये हैं....

श्री उपसभापति : ग्रभी इस पर ग्राप बहस मत करिये । ग्राप का प्वाइट ग्राफ ग्राईर क्या है ?

श्री रामेश्वर सिंह : : मेरा प्वाइंट आफ ग्राडेंर इसी पर है । बिहार में, उत्तर प्रदेश में कहीं खेती नहीं होती और यह सूखे का काल अटेंशन आप ने एक्सेप्ट किया है ।

श्री उपसभापति : यह प्वाइंट ग्राफ ग्राइंर नहीं उठता ।

This is not a point of order. Please resume your seat.

यह प्वाइंट ग्राफ ग्राईर नहीं है।

श्री रामेश्वर सिंह : उपसभापति महोदय, मैं जो बात कह रहा हूं उस को ब्राप ध्यान से सून कर ...

श्वी उपसमापति : जब ग्राप का टर्न ग्रायेगा तो ग्राप बोलियेगा ।

श्वी रामेश्वर सिंहः मेरा जो प्वाइंट आफ ब्रार्डर है उस पर आप व्यवस्था दीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat, Mr. Rameshwar Singh. I am standing. Please allow Mr. **Bhamidipatj to speak.**

in various parts 212 *of the Country*

मैं खड़ा हं ! अगर आप में जरा भी लिहाज है ग्रौर सदन की परम्परा का जरा भी ग्राप को ख्याल है तो ग्राप बैठिये। आप इस प्रकार से द्यशिष्ट व्यवहार करते हैं । ग्रभी मैं खडा हं इसलिये आप बैठ जायें । ग्राप कृपा करके बैठ जाइये। सदन की जो परम्परा है उसके ग्रनुसार जब चेयरमैन खडा होता है तो ग्रापको बैठ जाना चाहिए । यह शिष्टाचार का नियम है और जब कोई माननीय सदस्य उसका उल्लंघन करता है तो वह उचित नहीं है। यह प्वाइंट ग्राफ ग्राउंर आपकी तरफ से रेज नहीं हो रहा है । आपका जब समय होगा तो आप उसमें अपनी आवजर्वेशन कर सकते हैं, मुझे कोई ग्रापत्ति नहीं है । इस समय जिसने काल अटेंशन किया है उनको बोलने दीजिए... (ब्यवधान)

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, केवल एक मिनट में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं ।

श्वी उपसभापति : अगर माननीय सदस्य बार-बार उस चीज पर बहस करते रहेंगे तो सदन का समय बरबाद होगा आप जबरदस्ती उस पर बोल रहे हैं...

श्री कलराज मिश्र: श्रीमन्, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं केवल इतना ही कह रहा था कि कालिंग ग्रटेंशन जो हमने दिया था, मैंने स्वयं दिया था तो मैंने उसमें प्राकृतिक विपदा से, सूखे तथा वर्षा के कारण जो भयंकर क्षति हुई है, वह विषय रखा था ... (व्यवधान)

श्वी **उपसमापति** ः ग्रापका स्वीकार नहीं हुग्रा, यह दूसरा है ।

श्वी कलराज मिश्र : चूंकि मैंने भी दिया था, इसलिए मेरा भी नाम इसमें ग्रा गया है ... (व्यवधान) श्री उपसभापति : वर्था का पार्ट ग्रापका नहीं लिया गया है, सुखा का लिया गया है । इसलिए सुखा वाले विषय में आपका नाम है ।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : श्रीमन्, सेरा प्वाइंट ग्राफ ग्राइंर है कालिंग ग्रटेंशन के बारे में ।

श्री उपसमापति : कहिये क्या प्वाइंट ग्राफ ग्राईर है ।

श्री शिव चन्द्र झा : कालिंग अटेंशन मैंने भी दिया था । सूखे श्रीर बाढ़ से ग्रसित खेतिहर किसान भी होते हैं मरा भी इसी के मुताल्लिक है तो मेरा नाम इसमें क्यों नहीं ग्राया है ?

श्री उपसभापति : मैं इसको टेखूंगा क्यों नहीं हन्ना ।

SHRI KRISHNA MOHAN BHAMI-DIPATI: The statement of the honourable Minister is of a general nature. A severe drought situation is prevailing in the State of Andhra Pradesh. I do not want to politicise any issue. But I may submit that in spite of the massive Central assistance to the tune of nearly Rs. 68 crores no relief works were undertaken by the present Government after January, 1983. Due to the freezing of funds in February drought relief works as also works relating to the construction of bridges and other de-vatopmental activities have come to a grinding halt and most of the construction workers and workers engaged in the agricultural operations had to migrate to the neighbouring States for want of work. There is acute drinking water scarcity for the first time in most of the districts of Telan-gana and Rayalaseema and also in the upland areas of the coastal districts. The freezing of funds by the Government in February has resulted in a serious setback in the drinking water operation started by the previous Government which was in

in various parts of the Country

full swing particularly in the districts of Cuddapah, Nellore and Chittore, and for the first time in the century the twin cities of Hyderabad and Secunderabad are facing drinking water problem. Every year the Hussain Sagar from which the twin-cities' people get water, used to be deepened in the months oi February and March. But due to the freezing, of funds in February the deepening activity could not be done thereby the people of the twin cities for the first time in a century are experiencing drinking water problem. Due to the continuous drought conditions in Andhra Pradesh, the purchasing power of the middle-class people and agricultural labourers has fallen. Cooperative institutions and banks were collecting loans in a highhanded manner from the poor people, from tribals from drought-stricken areas of East Godavari and other districts. They need relief and protection from harassment. There is lot of apathy on the part of the Government to deal effectively with the drought situation in Andhra Pradesh. What the people want is action, and not dialogue, or high-sounding dialogues from the platforms; they want work.

Central assistance given to the States should be implemented properly and should be spent for drought # relief. The hon. Minister has just now said that he is sending a Central team to study the drought situation in Andhra Pradesh, to assess the magnitude and severity of the situation and basing on the recommendations of this team, quantum of assistance would be assessed. Sir, I had the occasion to go to Madras and I toured some villages. Tamil Nadu is facing the worst drought situation. I was told by the people that after getting independence Tamil Nadu has experienced 12 droughts. While the Centre is giving thousands of crores of rupees as Central assistance to the States to meet the drought situation in various parts of the country, and Tamil Nadu was also given so much

215 *Calling* Attention [RAJYA SABHA] to sei>eTe drought

[Shri Krishna Mohan Bhamidipati]

of money, the people do not know where that money was actually spent. When the Centre was giving massive assistance to various States basing on the recommendations of the Central team, I suggest to the Government to set up another team to tour the droughtaffected areas to see whether the amount of assistance was being properly utilised or not.

Droughts in almost all the States of the country, have become a recurring phenomenon. Supposing there is drinking water problem in a particular area, we try to meet the situation by digging wells, and so on. But when there is a drought situation, it means that no work is being carried on, even though Central assistance is given to the State. I would request the hon. Minister to consider my suggestion. Just giving Central assistance to a State will not be sufficient unless you see that the assistance given to a particular State is also fully and properly utilised.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: I have already said in my statement that because of unprecedented drought situation in the country a record level ceiling of expenditure upto Rs. 436.26 crores was sanctioned to IS States and one Union Territory, including An-dhra Pradesh and Tamil Nadu. The hon. Member mentioned about relief measures not being carried out effectively in Andhra Pradesh. Basically, we are concerned with financial assistance which is to be given by the Central Government to State Governments, and then implementation of all those schemes which are taken up as relief measures, is within the ambit and jurisdiction of the State Government. However, the suggestion made by the hon. Member is a welcome suggestion and according to latest guidelines, we have requested the State Governments to identify the needs of each and every, district while submitting their memorandum. So, I

welcome th_e suggestion and we shall certainly do as much as is possible.

SHRI R. MOHANARANGAM (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, there is a severe unprecedented drought situation prevailing in almost all parts of the country, especially Tamil Nadu, Andhra Pradesh, some parts of Maharashtra, West Bengjal and some other States. But Tamil Nadu is facing a very severe situation which has not been faced by it so far to my knowledge; but I have seen in Tamil literature that Tamil Nadu was facing drought situation continuously for twelve years in the earlier days. Now, the same situation i_s prevailing in Tamil Nadu. But the Tamil Nadu Government has taken all the necessary steps to meet this situation. The Tamil Nadu Government has asked for Rs. 220 crores to meet the situation. But the Central Government has sanctioned only Rs. 63 crores as ceiling expenditure. Throughout the country, all the State Governments asked for Rs. 3,000 crores. But the Central Government has sanctioned only Rs. 600 crores. As far as Tamil Nadu is concerned, as I said just now, they have sanctioned a ceiling expenditure of Rs. 63 crores. Whenever we have such drought situations, after giving Central assistance, they think that everything has been done. IT there is no water and if there are rains, automatically, the water problem will be solved. But things do not happen like that. We have to help the farmers so that they will be ready to face any situation even after normar conditions are restored. Sir, as far as Tamil Nadu is concerned, I would like to point out that in Tamil Nadu, more than 15,000 bore wells have been dug and we have also instructed all the Panchayat Unions as well as all the Municipalities to take necessary steps to meet the drought situation.

Sir, about a decade ago, a technical committee was appointed by the Government of India. This Committee

-visited almost all the southern parts of the country. They recommended that the West flowing rivers should be diverted to those States which are badly in need of water. I do not know what' exactly the Government of India has done on the recommendation of this committee, which was appointed ten years back. I would like to know from the hon. Minister what steps the Government of India have taken on the recommendations of this technical committee which was appointed a decade ago.

Then, Sir, the; rivers should be treated as national assets. This issue has been raised so many times on the floor of Parliament. All the rivers have to be nationalised. Until and unless all the rivers are nationalised, we are not going to solve this problem. As you know, in almost all the Sessions, we are talking about this drought situation. We are talking about the drought situation, the Ian- I guage issue and so many other issues. But no concrete action is being taken. As my hon. friend has just pointed out, even after so much money has been given in regard to Andhra Pradesh, Rs. 100 crores or so. I do not know why they say they are not &* a position to face the problem. One thing I would like to point out. As far as my State is concerned, even though you have fixed a ceiling expenditure of Rs. 63 crores, the Tamil Nadu Government is going to spend more than Rs. 400-500 crores. Even if you appoint the Auditor-General of this country to go into this, they cannot find fault with the Tamil "Nadu Government. We are going to spend five to six times more than what the Government of India is go-m* to spend to meet this grave situation.

Sir, in regard to the quantity of rice to be supplied by the Centre to the State, you know fully well, as I said just now, our State is facing a very bad situation. If you come to Tamil

Nadu, you will see the plight

of the people. Now, you do not have "time ecause the Session is going on.

in various parts of the Country

After 11th or I2th, kindly visit our State. You will find that so many people, thousands and thousands of persons standing in the queue not only to get rice but to get water. We are very glad that the hon. Prime Minister will be participating in the function v/hen our Chief Minister will be handing over Rs. 30 crores to the Chief Minister of Andhra Pradesh for the implementation of this historic scheme, namely, the Telugu Ganga scheme.

Now, Sir, I would like to know what steps have been taken by the Government of India to meet the situation. It is my duty to ask this. But it is also my duty to mention what steps our Tamil Nadu Government have taken. Sir. the public distribution system in Tamil Nadu is an excellent one. We have 70,800 consumer shops in our State. We have 1 crcre 18 lakh ration cards or what you call consumer cards. The entire State is covered by these consumer cards. Through this, we are in a position to supply rice to the persons who are in need of it. As I said ear-liei, we are badly in need of Rs. 220 crores. But only Rs. 63 crores have been sanctioned by the Central Government. About this North-East monsoon I have to say one thing, the Hon. Minister can give some reply. He i nn say that the Tamil Nadu Government did not send the report in time, they sent the report one or two months after that. Sir, the climate of the country is not the same. It differs from south to north. We are expecting rains only from the month of October to December. We wait for the rains till the end of December. After waiting till the end of December, we thought that definitely we were not going to get rains after that. So, only after that we could come to the con-elusion and we submitted our report to the Government of India asking them to send a committee. They have sent the committee only in the month of March and after getting the report. of the committee I do not know what steps have been taken by the Government of India.

[Shri R. Mohanaranyan]

So far Rs. 3000 crores have been asked for the entir_e country and out of thi_s only Rs. 600 crores have been sanctioned. During the 35 years of independence even though 280 irrigation schemes were sanctioned, only 30 schemes have been implemented. I do not hold the Government responsible for this, but certainly responsibility should b_e fixed o_n th_e persons who have failed to implement the schemes. This has disturbed the peaceful atmosphere throughout the country.

I pray that Rs. 63 crores for Tamil Nadu is not sufficient. Moreover, you are not giving the entire amount as assistance. Out of this one-third is assistance and two-third is loan. If that so, the Central Government should be liberal in granting Rs. 220 crores for Tamil Nadu State which is facing a grave drought situation.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: Sir, we are happy to get the account of work done by the Tamil Nadu Government as given by the hon. Member. Most of the time....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: They are asking for Rs. 220 crores. You reply to that point.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: I have already pointed out that it is a very unprecedented drought situation and we have sanctioned record level of financial assistance. The resources at our disposal are not endless. We have to keep the norms and guidelines in mind while takj ing a decision about the financial assistance which is to be given to the States. Taking into account the plan of action which has been submitted by the State Government to the Central the employment generation Government. and other programmes which programme they are going to undertake and then as per the norms and guidelines of the Seventh Finance Commission a decision is taken. For Tamil Nadu, for 1982-83 total non-Plan ceiling was R«. 8.52 crores and Plan ceiling *» R«-At the same time, fc* 17.87 crores. 1983-84 this ceiling has been I

in various parts 220 *of the Country*

raised to Rs. 45.33 crores. About the allocation of foodgrains, in the month of March we gave 34,000 metric tonnes, in April 50,000 metric tonnes and in May 65 thousand metric tonnes. There is a continuous increase in allocation. Hon. Member had also said that we are depending on the coming monsoon season. Fortunately whatever reports we are receiving are good reports. According to the Metereo-logical Department, they have forecast rains in the next two or three days. In parts' of Tamil Nadu which is a neighbouring State of Kerala and Kerala has alreadv On 29th April, Cochin received rains. received 6 centimeters of rain, Tri-vandrum 1 centimeter. Then again on 30th April, Cochin received 5 cms., Tri-vandrum 4 cms and Kotayam 1 cm. Again on 1st of May, Trivandrum received 3 cms of rain. So we are hopeful that within a week or so, the situation will be eased and as per their forecast, parts of Tamil Nadu will have rains.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Satya Pal Malik.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): Sir, my name is there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your names is there but you were not there when I called you.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: I had just gone to get some papers.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What can I do? Now the number has gone beyond your name.

श्री शिव भग्द्र झा :: बोलने दीजिये ।

श्री उपसभापति : कै से बुलाएं, झब, सब[ि]को बोलने दें पहले । झाप ऐसी बात क्यों करते हैं .

श्री बी॰ सरयनारायण रेड्डो : में जरा वाहर गया था . . (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right Yor wait for some time. You cannot betaken out of turn. You should be present here when you are called. You were absent. I am not at fault.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: That is why I am asking you to give me a chance.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You cannot ask at this stage. Mr. Reddy, there is a procedure of the House. If a Member misses his chance, he will have to wait. You missed the chance, still you wantto take advantage.

रेसे मैम्बरों से

कोई हमदर्दी नहीं है, जब चांस रहेगा तो बाहर घमेंगे ।

क बाहर भा माननीय प्रधान मली जो ने व अन्य मंत्रियों ने भी कहा है कि उससे और अपनी जानकारी के बिनाह पर मैं कह सकता हं कि इस वक्त देश में बड़ा भारों संकट सुखेकी वजह से है और मझ को इस बात का अफसोस जरूर है कि जिस बात पर पहले बहस होनी चाहिए थो उस पर देर से हो रही है लेकिन मझे इस बात की खशी है कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकारा है कि सरकार सुखे की जो मिकदार है जो ग्रेविटी है उसके बारे में पूरों तरह से चिंतित है। स्वयं मैं पढ़ रहा था सुखे को बाबत । स्वयं प्रधान मंत्रे जो ने कहा कि करोब 75 फीसदी हिस्से में देश में इस वक्त सुखे का असर है। नारायण दत्त तिवारो जो ने कहीं कहा है कि 12 सूबों में सूखा है। सरकार खद इन तमाम च जों को मान रही है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इनमें भी कई ऐसे सूबे हैं जिनमें कि तीन-तीन साल से सुखा है। राजस्थान में तो शांच साल से ज्यादा हो गये हैं लगातार सूखा है। ब्योंकि राजस्थान का किसान तो परम्परागत तरीके से सुखे का सामना करता आ रहा है सदियों से । उसके मुकद्दर में सूखा लिखा हुआ है। लेकिन बह भी सिर्फ तीन साल को प्लानिंग करता है। एक साल फसल ग्रच्छों होने के बाद वह तीन साल को तैयारी करता है। तीन साल वह

सस्टेन कर सकता है। तीन साल से ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता ग्रीर वहां पर पांच साल से लगातार सुखा है। यह शायद छठा साल है जो मेरी जानकारी है। बेहतरीन नागौरी बछडे, बेहतरीन मवेशियों को तिलक लगा कर लोग घर से निकाल रहे हैं। वे रास्ते में मर रहे हैं या फिर जंगल में मर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रीय अखवारों में आई है। जसलमेर, बाड़मेर और उसके पास जोधपुर जिलों में लोग घरों को छोड कर भाग रहे हैं। राजस्थान के लगभग सभी गांवों में पीने के पानी की समस्या है, पीने के पानी की कमी है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के इलाके में पानी की कमो है। संथाल परगना, बिहार में पानो की कमी है, मद्रास में पानी की कमी है कूल मिला कर स्थिति बहुत भयानक है। ग्रनाज की कमी वेस्ट बंगाल में भी है, 12 सुबों में है। पानी की कमी, ग्रनाज को कमी ग्रीर चारे की कमी इन तीनों मोरचों पर सरकार इतना ही कह कर बरी नहीं हो सकतो है कि हमने इतने रुपये की व्यवस्था कर दो है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में मंत्री जी यहां पर बयान देते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सारे मल्क को खाना देने के लिये नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में ग्रापके मिनिस्टर जो सिविल सप्लाई के हैं तीन बार वे बयान कर चके हैं इस सदन में वे कहते हैं कि हम सिर्फ साढ़े बारह परसेंट टोटल ग्रनाज लेते हैं जो सारे मुल्क में ग्रनाज बिकता है उसको सिर्फ वे सप्लीमेंट करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहंगा कि इस वक्त जो देश में स्थिति है सिर्फ यह कह देने से ही हमारा काम चलने बाला नहीं है कि देश में ग्रनाज के भण्डार भरे हुए हैं। ग्रापने ग्रमरोका से मंगाकर भरे हों, मैं मान लेता हूं कि भण्डार भरे हैं लेकिन इस समय देश में जिन हिस्सों में सुखा है वहां सबसे गरीब-ग्रादमी की परचेजिंग पावर इतनी नहीं

223 Calling Attention [RAJYA SABHA] to severe drought [श्र] सत्यपाल मलिक]

है कि वह खुले बाजार में ग्रनाज खरीद सके । उसको इतनो हैसियत नहीं है । श्रापको सार्वजनिक बितरण प्रणाली तो शहरों ग्रीर कस्बों तक रह गयी है। लेकिन मैं अगर मान भी लूं बहस के लिए कि उन गांवों में सार्वजनिक वितरण प्रणालो को व्यवस्था है तो भी उनकी परचेजिंग पावर नहीं है। सरकार का काम सिर्फ राज्यों को रुपया देने से नहीं चलने वाला है । ग्रापको एसरटेन करना चाहिए कि जिन इलाकों में सुखा है वहां के गांवों में हर परिवार से कम से कम एक आदमी को रोजगार देंगे और उसके लिए उसको पैसा नहीं बल्कि अनाज देने की व्यवस्था करेंगे । जनता पार्टी ने बहुत काम अच्छे किये, बुरे किये, लेकिन जो काम के बदले ग्रनाज को योजना थो, प्लानिंग कर्म, शन के ग्रुप ने, आपके योजना ग्रायोग_ने माना है कि वह बेहतरोन योजना थी। ग्रगर वह चालू रहतों तो ग्रलग से राहत के काम को जरूरत नहीं थी उससे खाना मिलता । तो मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हं कि जो भखमरो के समाचार हैं, बहुत निदयता को बात है मान्यवर, कि सरकार यह कह कर अलग हो जातो है कि मोतें भुखमरो से नहीं हुई हैं। जोधपूर में एक पटवारी को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया कि जसने यह लिख कर भेज दिया था कि फलां गांव में भुखमरी से मौतें हो गयीं। भुखमरों को मौत की परिभाषा करने की बात डा. लोहिया ने शरू की थी और वह आज तक दोनों सदनों में खत्म नहीं हुई है । सरकार कहती है कि भुखमरों से मौतें नहीं होती हैं । डा॰ लोहिया कहते थे कि ऐसों मौत की परिभाषा हो जाय । उनका यह कहना था कि लगातार कम खाकर, लगातार माल न्युट्रीशन का शिकार रह कर ग्रीर एकदम फिर ग्रनाज को और कमी के

in various parts of the Country

कारण तमाम बीमारियों से जव आदमी मरता है तो कोई न कोई कारण दूसरा हो जाता है लेकिन वह कारण भुखमरी से पैदा होता है । इसलिए आप इतना भर कहकर बरी नहीं हो सकते हैं । एक हजार ग्रादमी जैसलमेर में मरे, बांदा में लोग मरे हैं, छोटा नागपुर में मरे हैं । तो नम्बर एक मैं यह कहना बाहता हूं कि आप एसरटेन करें कि एक भी आदमो इन सुखाग्रस्त इलाकों में ऐसा न बचे कि जिसके परिवार को आप काम के बदले ग्रनाज की व्यवस्था न करें ।

दूसरा, मान्यवर मैं निवेदन करना चाहता हं कि जो फेमोन कोड है वह बहत सख्त है, ग्रंग्रेजों के जमाने का है। सारे देश में ब्रकाल है । मैं माननोय मंत्रों जो से जानना चाहुंगा कि कितने प्रदेशों को ग्रभी तक ग्रापने ग्रकालग्रस्त घोषित किया है। जो फोमौन कोड है वह इतना निर्दयो है कि ग्राप ग्रभावग्रस्त घोषित करते हैं, अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं करते हैं । क्योंकि अकाल ग्रस्त घोषित करने से आपको जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लिहाजा स्राप जब तक पूरो बरवादों नहीं हो जाती है तब तक अकालप्रस्त घोषित नहीं करते हैं। मैं जानना चाहता हं कि कितने सूबे ग्रापने अकालग्रस्त घोषित किये हैं और क्या आप उस फेमोन कोड को जो इस मुल्क की जरूरतों के म्ताबिक बिल्कूल गलत है उसको दलने को कोशिश करेंगे ?

अंतिम बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक स्टोन है कि हर सेशन में चाहें वह एक महोने का हो या दो महोने के फासले से हो, इस पर बहस होतो है । सुखा हिंदुस्तान के लिए

राष्ट्रीय शर्म की चीज बन गया है, सुखा हिंदुस्तान की रोजमर्रा की चर्चा का प्रश्न बन गया है। मैं ग्रापके जरिये सरकार से निवेदन करना चाहता है, चंकि अकेले आपके हाथ में नहीं है कि जो हिंदुस्तान में सिचाई परियोजनाएं हैं उनको ग्राप तत्काल पुरा करिये । ग्रभी सवेरे भी इस पर बहस हई । आप बड़ें। शान से कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे खान-सामे हैं, हमने एशियाड कर दिया, हम वहत बेहतरीन बैरे हैं हमने निगुंट सम्मेलन कर दियां। अब आप तलाश कर रहे हैं ग्रौर कोई चोज आपको मिले और आप वाना परोसने के लिए तैयार हो जायें। में कहना चाहता हूं कि इन तमाम बेवकफियों के कामों को ग्राप रोकिये और सिंचाई के काम को प्रायोरिटो दोजिए और उसके ऊपर रुपया लगाइये, यह मैं प्रापसे निवेदन करना चाहता ē 1

श्री झारिफ मोहम्मद खान : मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त को है, सरकार की तरफ से हम भी इस संबंध में पूरी तरह से इस पर नजर रखे हए है । इसके बारे में हमें पूरी चिता है और हर संभव प्रयास हमने किया है कि इस समय जब देश का बडा हिस्सा सुखे से ग्रस्त है उसमें हम राज्य सन्कारों को उस समस्या का मकाबला करने में हर संभव सहायता कर सकें । श्रीमन्, माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार यह कह कर अपने फर्ज से नहीं बच जतों कि हमने कितना रुपया या कितनी सहायता राज्य सरकारों को दो है । कानून के अन्सार हमारे कार्यक्षेत्र में यही आता है कि जो काम प्रदेज सरकार के कार्यक्षेत्र में आते हों और प्रदेश सरकारों के पास संसाधन कम हों तो उस कार्य को पूरा करने के लिए उस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार जो

in various parts of the Country

भो संभव सहायता हो वह जुटाये प्रदेश सरकारों को इन कामों को पूरा करने के लिए । उसी आधार पर हम प्रदेश सरकार से ज्ञापन ग्राने के बाद उस पर विचार करते हैं और प्रदेश सरकारों को सहायता देते हैं । अगर माननीय सदस्य प्रदेश सरकारों को इस बात के लिए रजामन्द कर लें कि हम केवल उन्हें सहायता हो न दें, बल्कि इससे ग्रागे बढ़ कर उनके यहां यह भी सुनिक्ष्चित करें, यह काम भी हम अपने हाथ में लें कि जिलों में या जो ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं. उसमें काम करने की सौधी जिम्मेदारी अपने हाथ में लें, अगर प्रदेश सरकारों को इस बात के लिए मनवां सकें, तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए उस पर विचार करना कोई ज्यादा कठिन काम नहीं होगा ।

श्री सरस्यपाल मलिकः इसका समुचित उपयोग हो रहा है कि नहीं ? आपके राज्य मंती साहब रथ ने उड़ीसा में यह कहा कि जो राहत कार्य आपकी राज्य सरकार कर रही है, वह नाकाफी है और गलत है । उन्होंने खुद अपनी प्रदेश सरकार को आलोचना की ।

श्री ग्रारिफ मोहम्मद खान : नहीं, मैं किसे। पार्टी को प्रदेश सरकार को बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो बंटवारे का काम है हमारे संविधान के अन्तर्गत... (व्यवधान)

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी (महा-राष्ट्र) : वह पोलिटिकल मामला है ।

श्री ब्रारिफ मोहेम्मद खान : मैं केवल उसी को बात कर रहा हूं, हमारो मजबूरों है कि हमें मानिटरिंग करना चाहिए, करने को कोशिश करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर यह सारा काम संवैधानिक दष्टि से प्रदेश सरकार के

227

Calling Attention *to severe drought*

[RAJYA SABHA]

in various parts 228 of the Country

आ आरिफ मोहम्मद खान]

ही अंतर्गत आता है और शायद जिस हद तक आता है, अगर उससे आगे बढ़ कर हमने देखने की कोशिश को, तो शायद तब प्रदेश सरकार के मामलों में दखलंदाजी का नाम दिया जाने लगेगा इसलिए मैं सिर्फ इतना हो निवेदन कर रहा था कि अगर उस बात के लिए कोई सहमति जुटा सकें, तो हमें उस संबंध में काम को अपने हाथ में लेने या देखने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी ।

दसरे काम के बदले अनाज योजना. ग्राज जो एन⇒ आर०ई० पी∘, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगर योजना ग्रौर जो सुखाग्रस्त क्षेत्र हैं, उनमें भी जो मजदूरी काम करने वालों को दी जानी है, उसका ग्रांशिक भुगतान एक किलोग्राम गेहुं प्रति व्यक्ति के हिसाब से किया जाता है ग्रौर इसलिए जो सहायता केन्द्रीय सरकार की तरफ से स्वीकृत को जातो है, प्रदेश सरकार को...(व्यवधान) जो सहायता केन्द्र सरकार की तरफ से प्रदेश सरकारों को दो जाती है, उस सहायता का निर्णय लेते समय जो गल्ला दिया जाना है प्रदेश सरकारों को, इस आंशिक वेतन के रूप में जो मजदूरों को दिया जाएगा, उसका भो निर्णय लिखा जाता है ग्रीर उसके संबंध में भी प्रदेश सरकारों को सूचना देदी जातों है।

SHRI AG. KULKARNI: Mr. Minister, when you are saying this, we agree that in the Centre it is so. But the Rural Development Ministry Report says that even 46 per cent of the grains is not distributed by the State Governments. And we are crying for the drought affected persons. You see there is a conflict between the two; perhaps Rao Saheb will know better. The Ministry of Rural Development Report says that 46 per cent only is distributed. हम क्या करें, हम रो रहे हैं। We are crying actually, Mr Minister. You are a young man. I have got hopes in you.

वाकी सब डिस्ट्रिब्यूट हुम्रा ही नहीं।

SHRI ARIF MOHD. KHAN: I am not talking only about the "National Rural Employment Programme. In addition 10 the NREP, financial assistance we give to meet the relief works.

श्री ग्रारविद गणेश कुल णीं: ग्राप चालाकी करके... (ब्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसका जवाब दे रहे हैं?

श्री ग्रारिफ नोहम्मद खान श्रीमन्, जो फाइनेंशल ग्रसिसटेंस है, उसके साथ-साथ मैंने कहा था कि

Allocation of foodgrains is also done, and the State Governments are informed of this allocation, and they can purchase. This does not come under the NREP. This is under a different head. This is an additional allocation. This may be true about allocation made under the NREP. What I am talking is about the programme under relief measures.

दूसरे जो केमीन कोड के संबंध में माननीय सदस्य ने कहा था, एक तो अकालग्रस्त या अभावग्रस्त किसी भी क्षेत्र को घोषित करना यह केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम में नहीं खाता है । यह प्रदेश सरकारों को ही करना होता है । प्रदेश सरकारों ने जहां कहीं फैसले लिए होंगे मुझे उस की सुचना नहीं है अगर चाहेंगे तो प्रदेश सरकारों से सुचना मंगवा कर भिजवा देंगे । पिछले कई दर्षों में फेमिन कोड में कुछ संशोधन भी किथे गये हैं जिस की विस्तृत जानकारी मैं इस समय नहीं दे सकूंगा और माननीय सदस्य चाहेंगे तो बाद में दी जा सकेगी ।

श्रीराम नरेश कुशवाहा*(उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश में कितना भयंकर सुखाः पडा...

229 *Calling Attention* to seuere droucM

230

श्री उपसमापतिः आप बैठिए, श्री भामडाः।

श्री हरी शकर भामड़ा (राजस्थान) : उपसभापति महोदय, बकाजी केवल पंजाब में नहीं हैं, 15 सूबों में हम सब प्रकाली हैं क्योंकि हम अकालग्रस्त हैं, वह वैसे अकालो है, हम अकालग्रस्त हैं इस लिए अकाली है। अकाल की समस्या पर हम रोज बहस करते हैं, लेकिन कुछ आधारभूत महे हैं जिन को अभी तक आप ने साल्व नहीं किया है । सब से पहली बात यह है कि ग्रकाल की भीषणता का सही ढंग से आकलन करने की जिम्मेदारी किस की है। राज्य सरकारें झाप से एक रकम मांगती है, संतलन राजस्थान ने 250 करोड मांगा है हमारे। यहां कितना भीषण जकाल है, जब कि आप ने आभी तक केवल 11 करोड रुपये भेजे हैं । इस बीच में 1500 लोग भुख से मर चुके हैं। स्वयं प्रधान मंत्री वहां जा कर आयी हैं। प्रधान मंत्री के वायस आ जाने के बावजुद आप की स्टडी टीम अभी वहां गयी नहीं हैं। राज्य की सरकार इस झगड़े में उलझी हई है कि वह कुपोषण से मरे हैं, दूषित पेय जल से मरे हैं, बीमारियों से मरे हैं या भूख से मरे हैं। लोग मर रहे हैं, आप की स्टडी टीम गयी नहीं है, प्रधान मंत्री जा कर ग्रा गयी हैं, उस के बाद जब सरकार को रिपोर्ट आयेगी, आप अपना पूरा रिकार्ड उठा कर देख लीजिए झकाल के बारे में आंकलन जो राज्य सरकार करती है केन्द्र सरकार ने कभी उस को स्वीकार बहीं किया है, पूरे तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया है। आप ने कहा कि हम उन कानूनों से बंधे हुए जो ग्राप ने बनाए है। आप उन कानुनों से बंधे हुए हैं, जो राज्य सरकार ने आंकलन किया है जस को आप स्र्दी 💠 तहीं करते, आप जो स्टडी टीम भेजते हैं वह भी आप के

कानून से बंधी हुई है इसलिए उस हिसाब से रिपोर्ट करती है। परिणाम यह होता है कि जो अकालग्रस्त लोग हैं वह आपके झगड़े में मारे जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इसका सही आंकलन करिए कि भीषण अकाल कहां-कहां है और जो कानून आप के मदद करने में रोड़े अटका रहे हैं मेहरवानी कर के उन को बदल दीजिए। पालियामेंट बैठा हुई है। आप पालियामेंट के सदस्यों की टीम भेजिए जो आप के सामने सही आंकलन पेश करे। पहले यह तो मुद्दा तथ हो कि कौन राज्य किस रूप में अकाल से पीड़ित हैं।

in various parts

दूसरा सवाल यह है कि राज्य सरकारों को इस सब के बाद जो ग्राप सहायता देते हैं यह कौन देखेगा कि ग्राप की दी हुई सहायता का समुचित उपयोग राज्य सरकार कर रही है या नहीं । ग्राप दे कर कह देते हैं कि यह हमारा काम नहीं है, मगर मैं ग्राप से निवेदन करना चाहता हू कि ग्रकाल के मामले में बड़े घपले होते हैं ग्रौर उन को रोकने के लिए जरूरी है—वक्त ग्रा गया है— कि केन्द्रीय सरकार उस में इन्टरफियरेंस करे ग्रौर देखे कि जितनी सहायता केन्द्रीय सरकार देती है वह ईमानदारी से ग्राकाल पीड़ितों पर खर्च होती है । इस के बारे में भी तय करना पड़ेगा ।

तीसरा बात रीजनल इम्बेलैंसज की है, असमानता की । आप देखिए कि राजस्थान में अकाल की स्थिति यह है, मैं उदाहरण के तौर पर आप को बता रहा हूं राजस्थान में जहां एक करोड़ 27 लाख अकाल से परित है, 23,372 गांव अकाल से पीड़ित हैं वहां आप ने 11 करोड़ रुपए दिए हैं। उस के ठीक सामने मध्य प्रदेश में आपकी रिपोर्ट के मुताबिक 80 खाख लोग प्रभावित हैं, वहां आप ने उन को 27 करोड़ रुपए दिये हैं। आखिर यह क्षेत्रीय असन्तुलन क्यों हो

231 Calling Attention [RAJYA SABHA 1 to severe drought

[थी हरिशंकर भामड़ा]

मान्यवर, आप ने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि केरल में मानसून आ गया है ग्रौर तमिल नाड् में ग्राने वाला है। यदि यही ग्राक्वासन देना है तो हम को भगवान के भरोसे छोड़िये। अगर मानसून से ही हम को बचाना है तो वह बचायेगा । लेकिन ग्राप क्या कर रहे हैं। मानसून पर जो आप की डिपेल्डेबिलिटी है उस को खतम करने के लिये आप ने कितना इरिगेशन करवाया है, इस की आप कल्पना करिये और उस के बारे में आप यहां ग्रांकडे दीजिए कि हम ने इतने परसेंटेज पर जो मानसून पर जो डिपेन्डेबिलिटी है उस को कम कर दिया है ग्रौर इतने राज्यों में हम झपने पैरों पर खड़े हुए हैं, जहां मानसून आये या न आये, हम वहां पर किसी को भूख या अकाल से मरने नहीं देंगे । उत्तर प्रदेश में पानी पीने को नहीं मिल रहा है। बांदा में पानी नहीं मिल रहा है। बिहार में पीने के पाना को समस्या है ग्रीर राजस्थान में हालत यह है कि पानी न मिलने के कारण जैसलमेर में और बाडमेर में जो मौतें हो रही हैं ग्रौर जिन को देखने के लिये प्रधान मंत्री जी स्वयंगयीं थी और जिन के लिये झगडा चल रहा है कि वे मौतें कुपोषण से हुई हैं या भूख से हुई हें या दूषित पानी से हुई हैं, वहां भी पानी की कमी है। मेरे पास लिस्ट है ग्रौर मैं कुछ नाम गिना सकता हुं जो इस प्रकार हें---श्रीमती भीखम कौर, श्रीमती जमानिया. श्रीमती इन्दिरा, श्रीमती फुलकूंबर और श्रो किसन सिंह ग्रौर श्री भैया राम भील, ये सब

लोग मरने के करीब हैं। हम ने टीम भेजी है। वहां लोगों ने घर सम्हाले हैं। एक दाना उन के लिये वहां नहीं है । लोग वहां छालों को उबाल कर और उन का जस एक दिन में दो बार पी कर अपनी जिन्दगी गजार रहे हैं, सिसक रहे हैं और मरने जा रहे हैं और ग्राप इस झगडे में पड़े रहेंगे कि यह कूपोषण से मर रहे हैं या बीमारी से मर रहे हैं या भखसे मर रहे हैं। आज वहां जो लोग मर रहे हैं उन के लिये केन्द्रीय सरकार को ग्रविलम्ब कुछ करना चाहिए चाहे वे उत्तर प्रदेश में बिना पाना के मर रहे है या राजस्थान में भख से मर रहे हों या कूपोषण से मर रहे हों या दूषित पैय जल से मर रहे हों। उन के लिये ग्राज कोई मेडिसिन की व्यवस्था नहीं है ग्रौर न पानी की कोई व्यवस्था है। जसलमेर में, राजस्थान में आप ने 64 टेंकर दिये, सरकार ने दिये और उन में से 20 या 25 खराब हैं। इस के ग्रलावा कुछ जगहों में वहां ट्यूब वेल लगाये गये हैं और उन में 70 परसेंट ट्यूब वेल काम नहीं कर रहे हैं। जहां ट्यूब वेल काम नहीं कर रहे हैं वे लोग जब कलेक्टर से कहते हैं कि हम को पानी नहीं मिल रहा है और इसलिये जाप हमारे यहां टेंकर से पानी भेजिए तो जिला प्रशासन कहता है कि जहां ट्यूब वेल लग च के हैं वहां हम टेंकर से पानी नहीं ले जायेंगे । ग्रगर ग्राप के यहां टयब वेल काम नहीं करते तो वह कहते हैं कि उस के लिये दूसरा प्रोसीजर है, उस के ग्रन्सार आप दरख्वास्त दीजिए लेकिन चंकि टयब वेल वहां लग च्के हैं, इस लिये टैकर वहां नहीं जायगा। इस तरह की टेक्निकल बातों पर आप की सरकार काम कर रही है और लोगों की जान के साथ खिलवाड कर रही है। लाखों की संख्या में गायें राजस्वान से पाकिस्तान जा रही हैं कटने के लिये । यह बात सही कही मलिक साहब ने कि प्राज वहां लोग

श्रपने पश्चग्रीं को छोड कर जा रहे हैं प्रौर वहां बहत से लोगों का जीवन ही पशुग्रों पर निर्भर करता है । तो जिन के पशुमर गये, जिन को उलटियां हो रही हैं ग्रीर बीमारियां हैं उन के लिये ग्राप डाक्टरों की राय ले रहे हैं कि वे कूपोषण से मर रहे हैं या बीमारियों से मर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में ग्राकाल की जो भोषणता है उस का ग्राप सही तौर पर आकलन कराइये और जो क्षेत्रीय **असंतुलन हो रहा है उस को** सन्म कराइये, वहां आवश्यक सहायता के काम कराइये और जो कानून आ डे आ रहे हैं उनको आप रह कराइये और जरूरत हो तो नये रू/नून बनाइये।

ओ ग्रारिफ मोहम्मद खान : Ĥ माननीय सदस्य को आपके ंमाध्यम से वताना चाहता हं कि कोई कानून आडे नहीं ब्रारहा है बल्कि उन कानुनों में ग्रोर कुछ ऐमे नियम है जिन के ग्रनुसार हम यह तय करने हैं कि प्रदेश सरकार से मिलने वाले जापन पर जो सहायता देने के लिये आते हैं, कितनी सहायता दी जाय । क्योंकि इमारे संसाधन सीमित हैं, असीमित नहीं हैं कि जितनी मांग की गयी उतना रुपया हम राज्य सरकारों को देने में कामयाब हो सकें। स्राज ऐसी स्थिति नहीं है । अपने सीमित संसाधनों को देखते हुए कुछ नियमों के अनुसार ग्रौर अपनी टीम को भेज कर वहां की स्थिति का परा आंकलन करा कर उन को सहायता देने का निर्णय किया जाता है । वहां का परा आंकलन कराकर यह तय करते हैं कि वहां क्या क्या काम कराना हे । माननीय संदस्य ने राजस्थान के सिनसिने में कहा है । 1979-80 में वहां 18 करोड़ 75 लाख की सहायता दी गयी ग्रीर 1980-81 में 40 करोड़ 지수는 지수 방법 제 없는 것 같은 구성이다.

in various parts 234 *of the Country*

70 लाख रुपये की सहायता दी गयी। 1981-82 में 87 लाख और 1982-P.M. 83 में 90 लाख, अर्थात् पिछले चार वर्ष में कुल मिलाकर 213 करोड़ 72 लाख रुपया सुखे से प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए दिया गया है केन्द्रीय सरकार की लरफ से । राजस्थान सरकार की मदद के लिए इस में यानी चालू वित्तीय वर्ष में सितम्बर तक जो खर्चा किया गया है ।

श्री हरी शंकर भाभड़ा : श्रीमन्, जहां पहली बार अकाल पड़ा है और जहां पर दो बार, तीन बार, चार बार या पांचवीं बार अकाल पड़ा है वहां की सीबियरिटी ज्यादा होगी कि नहीं । आप के आंकड़े पिछले वाले बता रहे हैं। लेकिन अकाल की भीषणता वहां ज्यादा होगी कि नहीं जहां पर चार.-पांच साल से अकाल पड़ रहा है । वहां कितनी अधिक सहायता दी गई ?

थी आरिफ मोहम्मद खान : माननीय सदस्य की चिन्ता ठीक ही है । हमने खुद ग्रपनी चिन्ता व्यक्त की है ग्रौर जितनी ज्यादा से ज्यादा ग्राथिक सहायता सम्भव है वह सहायता हम उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। 1983-84 के चाल वित्तीय वर्ष में जैसा में बता रहा था, 13 करोड़ 16 लाख इपया सितम्बर तक खर्च करने के लिए स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा दी गई है। इसका एक ही उद्देश्य है कि उन क्षेत्रों में जहां कई सालों से सुखा है या इस वर्ष सुखा है, जहां के लिए यह कहा गया है कि वहां खाने के लिए अनाज नहीं है, फेयर प्राइस शाप्स की दुकानों से झनाज उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन लोगों की कय शक्ति नहीं है तो ऐसे लोगों की कय शक्ति बढाने के लिए, उन्हें इस लायक बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में SHRI ERA SEZHIYAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, the honourable

[श्री ग्रारिफ मोहम्मद खान]

अभावग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी तौर से ये संसाधन राज्य सरकारों को उपलब्ध कराये जाते हैं। हम कोघिश करते हैं कि उसका उपयोग ठीक ढंग से हो।

Minister, while making his statement, again and again stressed upon the fact of limited resources with the Central Government against the demands and the requirements of the States to meet the unprecedented drought situation of a significantly higher order. While we are on this one, I would like to impress upon the Government and also the Minister that the resources available with the States are in a much worse condition and even in normal times they are not able to cope with their normal responsibility put oa them and in a situation of unprecedented drought like the present one, you can very well imagine the position of the States which the exigency of the situation has put them in. That is why I say that priority should be given to this. In spite of the limited resources available with the Central Government, a re-ordering of the priorities is required to be done and everything should be done to see that the people get at least drinking water and the basic amenities and the minimum needs in the drought-affected area.

Sir, when the Minister was concluding his reply to the first Member, he said something hopefully about the setting in of the southwest monsoon in Kerala and he also said that it might help Tamil Nadu. All the westflowing rivers get their waters and the reservoirs get filled up because of this monsoon in Kerala. As you are aware, Tamil Nadu depends on the northeast monsoon and the south-west monsoon benefits those areas west of the western ghat only and the major portion of Tamil Nadu lies on the eastern side of the western ghat and, therefore, we have to wait for the north-east monsoon only to bring some rains to the parched areas of Tamil Nadu. We cannot simplify

in various parts

south-west monsoon.

He has also said about the various steps taken. But, as a person coming from Tamil Nadu, I feel very much about this. But the starvation deaths in Rajas-than and water not being available in many parts of the country, I thnik, put us in a state of great agony and it is a very sorry of affairs that even after 35 years of independence we are not able to give even the basic requirement of water to our own people. I think this is where we have failed. As a whole, the Government and those who are in charge of planning have failed. We have to admit this. Unless we give a high priority, it is no use. I think these five star hotels and flyovers can wait. First of all, drinking water to the common man in the distant villages should be provided. That should be given thet highest priority. In the matter of ceilings also, I request the Minister and the Government to raise the ceilings.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You know the constraints also of resources.

SHRI A. G. KULKARNI: What constraints? *{Interruptions)*

SHRI ERA SEZHIYAN: Mr. Deputy Chairman, Sir, therefore, I request raising of ceilings. My point is, stop this extravagant expenditure on five-star hotels and fly-overs. Let them wait. Highest priority should be given to drinking water. Even 'pure drinks' can wait, Campa Cola can wait, Campa Cola man can also wait for some time. But there is the poor man in the village who does not have

SHRI A. G. KULKARNI: The poor man can wait; there is nobody to care for him.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish.

SHRI ERA SEZHIYAN; First was to give a high priority to drinking water. Will the Government come forward to give a higher priority than hitherto allow-

237 Calling Attention [4 MAY, 1983] to severe drought

ed for supply of drinking water, not only to problem villages, but in many of the problem habitations in cities and villages; even in a city there may be posh areas and slum areas where water is not available.

Second thing is about the supply of drinking water to Madras. I want to make one appeal to everybody. This morning an hon'ble Member also raised a point whether the Chief Minister of And-bxa and Tamil Nadu got a clearance from the Centre before putting this agreement of Krishna water to Madras. First let m come to an agreement. All this time this has been waiting. In the year 1963 the Gulati Commission's report provided 15 TMC to Madras. But all this time it was allowed to gather dust. In the year 1976, on February 15th Mrs. Gandhi came to Madras at the time of emergency and she gave her blessings and said that Krishna waters are coming by canal. Seven years have passed but Krishna waters have not come by canal. Krishna waters are now being taken by rail instead .of canal. The agreement would help.

, Let us not put small hindrances in the way.

Then, they also said in paragraph 6:

•'The Hon'ble Members must be aware of the efforts being made by the Railways to augment the water supply in Madras city by transporting water from Andhra Pradesh."

That is a good thing, We are thankful for all the help that has been given. But there are limitations also. Every day the railways bring about 3 lakh gallons of, water. The requirement of Madras city is 450 lakh gallons every day. I would also impress upon the Minister that it will be good if the Central Government manages some of its own requirements. Even the Railways in Madras consume 15 lakh gallons a day, fertilizers and refineries 10 lakh gallons, each Madras Port Trust 5 lakhs CRP 2J lakh tonnes. About 42.5. lakh gallons every day the Central Government establishments alone consume at Madras. But we are thankful for whatever they have done in this matter. We appreciate that 3 lakh gallons come every

in various ports of the Country

day. But that is not whole end of the story. Two Central Ministers came with all the fanfare to receive water by rail but the impact is not even .6 per cent of the entire supply.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: More water can come by ship.

SHRI ERA SEZHIYAN: Yes, yes, some can come by air also.

Sir, I would appeal to the Minister for increasing the funds, raising the ceiling limit of the funds, to be given to Tamil Nadu. Traditionally, whenever there is a serious drought or famine, massive relief works are started like laying the roads, digging canals etc. There is also the food for work programme. Will that be augmented as far as the drought affected areas are concerned? There is also the drought prone affected programme. Will that be given a special and higher priority than it has been given so far?

SHRI ARIF MOHD. KHAN: Sir I share the sentiments and the concern which the very senior and hon. Member has expressed. However, as far as the questio* of priorities is concerned, it is projected in the State's Annual Plan. Under drought relief programme, the Central Government only supplements those priorities and plans of the State which have already been outlined. As regards the starvation deaths in Rajasthan, as soon as we received these reports, the Central Government got in touch with the Rajasthan Government and the information which we have received from them is that according to their reports there has not been a single starvation death in any part of Rajasthan.

SHRI ERA SEZHIYAN: It is deaths due to mysterious disease.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: I do not know about the mysterious disease.

SHRI ERA SEZHIYAN: Hunger.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: If the hon. Member gives me any definite infor mation about any part, then I assure that weshall ...

	(व्यवधान) जो भी निश्चत हुग्रा			
है, मैं	ग्रापको	विश्वास	दिलाता	हूँ कि
उ स के ^ह	सम्बन्ध	में हम	प्रदेश 🏾	सरकार

[Shri Arif Mohd. Khan.]

in various parts 240 *of the Country*

they have alr 10,000 shall Railways are

को दुबारा लिखेंगे और उनसे कहेंगे। मैं उसके सिलसिले में पहले हो कह चुका हू कि अगर इस संबंध में कहीं कोई निश्चित जानकारी मिलेगीतो उस जानकारी के आधार

पर हम प्रदेश सरकार से जरूर ही कहेंगे कि

इस पर वे अपनी रिपोर्ट दें और हमें बतायें

टिप्पणी कि उसकी क्या ਡੈ Secondly, Sir, about Madras city, in 1982-83 we had given Rs. 3.25 crores, and for 1983-84, this is not for the entire year, we had given Rs. 1.64 crores. These funds have been earmarked for providing drinking water in the drought affected areas. For the rest of the State Rs. 13.59 crores was provided in 1982-83 and in 1983-84, up to 30th June. Rs. 12.77 crores had been provided. The total comes to Rs. 16.84 crores and Rs. 14.41 crores, upto 30th June, 1983-84, which comes to Rs. 31.25 crores.

Then, Sir, the hon. Member had also mentioned about my expressing the hope that rains will come soon and they will benefit Tamil Nadu. I am not expressing any hope though we are always hopeful. It is the forecast of the Indian Meteorological Department. They have based their forecast on the basis of the rains which Kerala has already received.

SHRI ERA SEZHIYAN: Only in fringe areas adjoining to this area. It will be minimal.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: That is why I have said in parts of Tamil Nadu, and not in entire Tamil Nadu.

Well, Sir, I would also like to mention that though doubts were expressed that Red Hill, Poondi and Cholavaram are likely to go dry in another four weeks, the State Government are confident of meeting the drinking water problem in Madras city, up to the next monsoon, with the help of II thousand filter points as well as with the help of transportation of water and keeping it in storage tanks in different places in the city. There are already 1800 such storage tanks serviced by 190 lorries. As far as usual areas are concerned, the State have a target of sinking 20,000 tubewells out of which they have already sunk 10,000 and the balance 10,000 shall be completed by the end of June. Railways are transporting 3 lakh gallons of water per day from Andhra Pradesh. This supply is likely to go up to 5 lakh gallons per day.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think we cannot complete it because there are three more Members to speak. The debate will continu after lunch.

सदन की कार्यवाही 2.15 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

The House then adjourned lor lunch at sixteen minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at eighteen minutes past two of the clock.

[The Vice-Chairman (Shri R. R. M«-rarka) in the Chair.]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R R MORARKA): We will resume the discus-sion on the Calling Attention.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Mr. Vice-Chairman: Sir, about this. drought situation, I think, we have discussed this issue several times in this House and we have' also got assurances from the Government. This time also, the hon. Minister has come out with a statement and I would like to draw the attention of the House to the last para of the statement wherein he has said:

"I wish to assure the House that Government are fully seized of the situation and will extend all possible assistance to the States in this hour of distress."

But it appears to me, though the assurances are there, there is a very big gap between the words and the deeds of the Government. Previously also, we have discussed this issue and the same assurances were given to the Members. But ultimately, most of these assurances were belied. Now, Sir, I would like to draw the attention of the House to some points as it is not possible to discuss all the points in-detail. I would concentrate myself on one or two points. Several States have been afflicted with this drought situation. It is unforeseen drought that the country has.

been seized with, but in Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, Rajasthan and Bihar v here the situation has become very much acute I find that the Central assistance to the States has not come up to the expecta-1 an. For instance, I will cite the instance of Kerala. In respect of Kerala the Government has committed to supply 1.35 1 ikh tonnes per month, but it appears, that gradually this supply has been reduced to 90,000 or 95,000 tonnes and in the year of drought no additional supply las been made. Here the assurance is that the Government is there to stand by the States in their distress, but in this i:ase even the earlier commitment is not being kept and the supply is month by month dwindling.

In respect of West Bengal I would like <i point out that the drought situation West Bengal Gov here was very acute. ernment drew the attention of the Central iovernment and the Central team, has also visited the State more than once. The West Bengal Government has told the that their require Central Government ment of foodgrains per month is 4 lakh tonnes. With less than 4 lakh tonnes of feodgrains West Bengal Government would not be able to meet the situation. But the Central Government has not increased the quota' from the earlier 2.50 lakh ton nes. This is the quantity being given to 1981 and as a result West Bengal since of this there is a big shortfall between the supply and the dmeand. In view of this, I do not know how the State Gov ernments will be in a position to face the drought situation. Moreover, I find that when the Central supply was inadequate, the West Bengal Government proposed that they should be allowed to import 3 foodgrains lakh tonnes of from sur plus States through the West Ben gal Essential Commodities Supply Corporation If the Centre was not giving adequate supply, they should have permitted the West Bengal Government to import foodgrains from other surplus States, but even that was refused by the Central Government. permitted They West Bengal to import only 15,000 tonnes from Punjab. I do not know what is the reason for this, what has stood in the way West Beng.il to purchase of permitting rice from other surplus States when the

in various parts of the Country

State was suffering from acute scarcity of rice and wheat. I would like the hon. Minister to kindly explain this point, why the Government has not permitted the West Bengal Government to buy-rice from surplus S'ates. At least the Government should have per milted the West Bengal Government to buy 3 lath tonnes from surplus States through the West Bengal Essential Commodities Supply Corporation. I would like this point to be clarified by the Minister.

Then, Sir, in the statement it is said that the Central teams have visited different States, like Kerala, Bihar, West Bengal and other States. It has also been said in the statement that during the current year an amount of Rs. 8.53 crores has been given to Bihar as an additional assistance, but as regards other States nothing has been mentioned. I would like to know from the Minister, what was the total amount that was demanded by West Bengal from the Central Government in terms of relief for drought situation in the State and what is the amount given by the Central Government to the State? What is the gap between the demand made by the West Bengal Government and the assistance given by the Central Government? I would like to know these figures from the hon. Minister'

The other point is, I would like to know from the Minister, what is the priority fixed by the Government in meeting the drought situation, that is in respect of supply of foodgrains and arrangement for supply of drinking water?

My point is this. When the States are facing acute scarcity and shortage of foodgrains and the Centre is not in a position to send adequate supplies to the States we find that instead of importing rice and wheat from other countries, Government is spending money on importing luxury goods from other countries I would like to know from the Government what is the priority in this drought situation? Is it their priority to import foreign luxury goods from foreign countries or to import food-grains from foreign countries so that our people are fed, our people are not starved, our people do not die of hunger? What is the priority? And

243 Calling Attentio?i

in various parts 2 of the Country

[Sbri Sukomal Sen]

why is the Government not importing foodgrains and why they are importing luxury goods? I would like the Minister to clarify this. I also hope that the actions that will be taken by the Ministry will be duly comxnunicated to the Members of Parliament so that the Members of Parliament are kept informed of what is happening.

My last point is, on the 25th of March of this year, many of us in the Opposition protested against the attitude of the Government, against failure of the Government in meeting drought situation. At that time the Government came out with a statement. I would like to know since 25th of March when we protested against the attitude of the Government, what has been done by the Government to meet the situation? This statement is not clear on that, I would like to know what developments have taken place since we protested against the failure of the Government. Thank you, Sir.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: The hon. Member has specifically raised the question about Kerala and West Bengal and he has also tried to know the demands which were projected by the State Governments and the assistance sanctioned by the Central Government and the gap between the two. This is a very detailed document. Sir, if you permit me, I can lay it on the Table of the House, or I can send it later t_0 the Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Yes.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: This gives the memoranda of demands which came from the State Governments and the_n the final decision taken by the Central Government and the ceiling which was sanctioned.

As far as the question of West Bengal Government buying surplus rice is concerned, you will appreciate that it would be better if the question ' is addressed to the Food Ministry instead of the Agriculture Ministry.

SHRI SUKOMAL SEN: But you are replying to the Calling Attention Motion. You must be prepared with facts.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: No. **Sir**, surplus rice does not fall within my jurisdiction or the jurisdiction of my Ministry. Basically I am concerned with the relief measures which are being taken by the State Governments, the assistance which they have sought from us and after examining their proposals and the action plan which they have formulated we take a decision according to the norms and regulations set forth by the Seventh Finance Commission and then a decision is taken keeping in view their demands and the resources which are at our disposal.

Sir, the hon. Member has also raised the question of priorities, what priorities,¹ Government has tfixed to deal with the situation? As I have already mentioned in my statement, Government has sanctioned a record level of financial assistance to tin-State Governments to meet the problems created by the drought. Sir, if you permit me, I can give the figures as well. During 1982-83, the total figures are Rs. 436.26 crores and this is in addition to Rs. 345 crores which was given to the State Governments to complete the relief works during the floods. About Rs. 5.51 crores were given to those who were affected by hailstorms. Whatever assistance has been given is record assistance and this is so only because we feel that an unprecedented situation obtains in the country on account of drought etc.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, the unprecedented drought situation has not raised consciousness of various State Governments. The situation in my State of Maharashtra is that public co-operation is not taken by the Government.

There are many organisations, social organizations with representatives of people, but the Government thinks that only they can solve the problem. The situation is worsened because of there being virtually two Chief Ministers in our State. To study the drought situation only officers go. No proper programme is implemented. Only recently a meeting was held in Nagpur to' consider the question of damage to orange crop, damage caused by shortage of water. A large number of officers attended that meeting and a sum of Rs. 50,000 was <=pent on that but no concrete proposal came out.

Mr. Vice-Chairman, in Maharashtra, more than 17 districts are affected by drought, not only in Marathwada and Vidarbha but also in western Maharashtra, areas like Pune and Sangli. The effort which is required to be made On a war footing is not being made. In my area of Vidarbha, 17.000 acres of land are under orange cultivation. Oranges have been badly affected because of shortage of water; and it is estimated that crops worth more than Rs. 100 crores have been damaged by this and the trees are dving. A large number of photographs has appeared in the Press all over India. Though there is 43 per cent underground water in my State, there is no attempt to tap water. There is a general feeling that because of the infighting in the State, it is not taeinrr looked after seriously as it should be. Sir, it is surprising to find that the Central Government thinks that it has done its job by giving some Central assistance. The Maharashtra Government had asked for assistance worth Rs. 154 crores of rupees to meet the drought situation. That was the first proposal made. The Central Government has given Rs. 59 crores only as assistance, hardly one-third or one-fourth.

Earlier, one of the Members from Andhra Pradesh said that the Andhra Pradesh Government is misusing the funds and a central inquiry committee or commission should look into it. I

in various parts 2 *of the Country*

think the suggestion i_s mischievous. As rightly said by the Minister, it is for the State Governments to implement the programme of drought relief.

The Central Government should come to their aid and $^{\rm no}{\rm t}$ merely to find fault with them. Therefore, Sir, I would like to know on what basis they have given this onefourth assistance. Constraint of resources is not the only reason. In addition to that, they have got the guidelines. Only officers I do not know whether the State go. Agriculture Ministers' Conference was held and what their recommendations were. My first question is: when were these guidelines for giving financial assistance to the States fixed? Why is it one-fourth or onerfifth of what has been asked for is granted? The guidelines are old and there is need to radically change them in view of the unprecedented situation about drought in the country.

Sir, in *my* State there is not only shortage of drinking water but there is also shortage of fodder and food-grains. Under the Employment Guarantee Scheme, the assistance people in my State are getting is Rs. 2 per day. When Mr. Sharad Pawar was the Chief Minister, wheat at 30 paise a kilo was supplied. There is need to give them more in terms of jouxir and wheat so that they can utilize it and sustain themselves in the situation. I would like to know whether he has increased the loodgrains quao-tity to be given to the Maharashtra State in this connection.

Lastly, the third question I want to know is whether there is any programme of having more wells, about which there is a mention in paragraph 5, particularly in the areas where we have got orange cultivation where there is much damage if there is no water supplied. There will be loss also of trees and other things. I would like to know whether they have a programme for preservation of fruit trees and orange cultivation or other cultivation on a large scale in Maharashtra. Lastly I would like to know

247 *Calling Attention* [RAJYA SABHA] *to severe drought* [Shri Shridhar Wasudeo Dhabe].

whether any Minister has visited the State or it has been left to a team of Central officers to discuss the matter and whether they have discussed the matter with the Chief Minister or other Ministers of the State. What is the assistance given to Maharashtra and what is the quota of foodgrains supplied?

SHRI ARIF MOHD. KHAN: Sir, I have stated that we take decision according to the guidelines and the resources which are available to us. I have never said that the guidelines come in our way. They do not come in our way- In fact, they help us to adopt a uniform policy while taking decision for sanctioning a ceiling of expenditure in respect of the States which are affected by any natural calamities. Sir, these guidelines were mainly determined by the Seventh Finnace Commission. Again whether they are guidelines or rules or whatever they are, they are framed keeping in view the means and resources which are available to us. That is specifically for the purpose of helping us t₀ allocate it in a uniform manner.

Sir, about the second question, I can give the details of the assistance which has been sanctiontd to the Maharashtra Government.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: And the foodgrains supply.

SHRI ARIF MOHD. KHAN-. Yes, I am giving the foodgrains supply figures.

During 1982-83 in regard to Maharashtra, the total Plan and non-Plan ceiling sanctioned by Cetral Government was Rs. 56.38 crores. And, Sir, for expenditure during the current year, that is up to Juno, 1983, to continue the relief works, the sanction was for Rs. 11.63 crores.

Sir, the foodgrain_s supp]y for Maharashtra In December 1982 were 4,250 metric tonnes; in January, 1983 3,700 metric tonnes. The information for the period after January, Sir, I will make 248

available to the hon. Member. This is not with me now.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: What was the demand from the State Government? That also he should tell. Unless you give u_s the demand and what you have supplied, these figures have no meaning.

SHRI ARIF MOHD. KHAN; If. you, are keen to know, I will certainly make it available to you.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: My questien was about the ' orange cultivation. The trees are drying. What special efforts are being made to save the tree_s in 17,000 acres of land in Vidarbha area?

SHRI AHIF MOHD. KHAN; As per the rules and the guidelines, we cannot take any action *suo mota*. A memorandum has to come from the State Government, and after wc receive one, therr, we depute. Sir, *no* memorandum of the Maharashtra State is pending with the Central Government.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, I put only one question because already my party colleague has already spoken. I want to know from the hon. Minister exactly how many villages have been affected. As per the report of the Maharashtra Government on the villages affected by the water shortage, if I mistake not, which you you will confirm or deny, as per the information given to us by the Maharashtra Government, 14,000 villages have been affected. Out of them, the Government is trying to supply water for 8000 villages. The total demand made by the Maharashtra Government apart from Rs. 159 crores for the total drought operations, is Rs. 29 crores for the water shortage. Mr. Minister, perhaps we all sitting in Delhi do not know what is the impact of the water shortage. People are dying. They are not dyint; for food. Food is short, but they are dying because there is no water to drink. They demanded about Rs. 29 crores. How much exactly have you sanctioned? I ask this

because you will again in your sweet voice and laughing mood say that you will supply. But the impact today will go away. God knows whether you will meet me or I will meet you. But we will make some efforts, this is a very severe drought that we are having. If you want any assistance, you can take it from office. There is no drinking vour water. And when a sum of Rs. 29.6 crores has been asked by the Maharashtra Chief Minister, not even Rs. 9 crores has been given. At present that is the biggest worrv of the Maharashtra Government. Similarly, Mr. Minister, my friends, Mr. Bagaitkar and Mr. Dhabe, have stated about the human inputs in Maharashtra. The in-fighting in your party and the Chief Minister being at loggerheads with the Deputy Chief Minister has made a mockery of the drought.' I assert it has made a mockery of the drought. For heaven's sake, improve the human inputs at least. The administration has to be improved.

SHRI' ARIF MOHD. KHAN; Sir, the question of providing drinking water should be reflected in the regular Plan of any State Government.

SHRI A. G. KULKARNI: No, Mr. Minister, you are making a mistake again.

SHRI ARIF MOHD. KHAN; Let me complete, and then he will have the right to question me again.

SHRI A. G. KULKARNI: Sorry to have bothered you.

SHRI ARIF MOHD. KHAN; Thank you very much. I am very sorry. You are a very senior Member. But I wanted to complete my reply. 1 was telling that in the first memorandum which was submitted by the Maharashtra Government, in fact, this demand was -not projected at all because this should be part o* ...

SHRI A. G. KULKARNI: What is this? Do you stand by your statement?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Order, please.

in various parts

of the Country

SHRI ARIF MOHD. KHAN; Please, let me complete. I am coming specifically to that point. We received a supplementary memorandum from the State. I wa\$ coming to that. Somebody must have suggested it at some stage and "then we received a supplementary memorandum. And this point I am making because of the other question which the very senior hon. Member has raised about the human input. I believe that the Maharashtra Government, despite whatever the; hon. Member has said, have taken up the case for financial assistance from the Central Government very forcefully and very effectively. In fact, there are not which many States gave a suplementary memorandum seeking financial assistance to provide drinking water to the problem-villages. The Maharashtra Government has submitted a memorandum and we have already taken a We have sanctioned financial decision assistance

SHRI A. G. KULKARNI: How much?

SHRI ARIF MOHD. KHAN: That I will make available to you in a few minutes. But this is again keeping in view the resources which are available to us.

SHRI A. G. KULKARNI: No, Mr. Minister...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Order, please. Mr. B. Satyanarayan Reddy.

SHRI A. G. KULKARNI: Only a clarification. At the outset, Mr. Minister vou said that the Maharashtra Government in their first memorandum has not made any reference about the shortage of drinking water. That is what you said just now. And you said that because of the human inputs, as you think they are better, they made a supplementary memorandum. Now every Government has made three memoranda. Why

251 Calling Attention [RAJYA SABHA] to severe drought

[Shri A. G. Kulkarni]

are you worried about that? You ask Mr. Vijya Bhaskara Reddy He has submitted three memoranda. Don't give a certificate to a dying party. Why « r_e you worried about it? But, Mr. Minister, let me be very fair with you. In the first memorandum, the demand was there for money for shortage of drinking water, for Rs. 11.9 crores Then they increased it to Rs. 29.6 crores. And you have sanctioned only Rs. 9 crores, which is a flea-bite for meeting the shortage of water.

SHRI ARIF MOHD. KHAN; Sir, what I meant was that in the first memorandum they certainly had sought assistance for making drinking water available. I was saying in the supplementary memoranda they identified the problem villages and this was something new for us. In fact, under drought relief this kind of assistance was not asked for by any other State before the Maharashtra Government asked for it. This is the point which I was making. I was not saving anything else. Normally whatever memoranda comes to us, there is a provision and we also, while sanctioning financial assistance, keep a provision for making drinking water available to the problem areas.

SHRI B. SATYANARAYAN

REDDY; We are discussing a very serious problem that' has arisen due to acute drought situation in different parts of the country, especially in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Rajas-than, Bihar and other parts of th^ country. At the outset I would like to say that instead of discussing this acute drought situation, some of our Members, by taking advantage of this Calling Attention Motion, tried to make some allegations against certain Governments; especially, my friend, Mr. Krishna Mohan Bhamidipati, while speaking on this Calling Attention in the morning, made unnecessary, uwarranted and useless allegations against the newly-formed Telurui Desam Government, in Andhra Pra-

in various parts

of the Country

desh. I stoutly refute those allegations and I say that this Government has come only three months back. All these 30 years Congress (I) party was in power. What were they doing? This new Government has come into power with the help, support, of the overwhelming majority of the people of Andhra Pradesh against the corruption, misrule and mismanagement oi the previous Congress-I Goverrunenl which was his. Here is the Telugu Desam Government which has come into power barely three months back headed by Mr. Rama Rao. Mr. Rama Rao decided to put an end to the corruption, misrule and the mismanagement of the previous Government. He has taken all the necessary measures to put an end to the poverty, drought conditions and suffering that the people of Andhra Pradesh have been experiencing. Recently, as yoti know, most areas of Telangana, Rayalaseema and other parts of the State of Andhra Pradesh are badly affected by drought. In order to meet this situation he has taken a historic decision in cooperation with the Chief Minister of Tamil Nadu Shri M. G. Ramachandran. The Chief Minister of Tamil Nadu. Shri M. G. Ramachandran and the Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. T. Rama Rao, have entered into a historicagreement for supply of Krishna waters to the Madras City; at the same time this will supply water to the drought affected areas of Rayalaseema. Shri Rama Rao has also taken measures to have Sri Ram Sagar Left Canal Project and also the 8ri-sailam left and Right Canal Pro.i.>:t> in order to meet the drought situation in the State. I would like to know from the Centre whether, i_n order to meet permanently this drought situation in Andhra Pradesh and also in the rest of the country, any permanent measures are going to be taken by the Central Government. The State Governments are trying their best to meet the situation. At the same time the Centre also has a responsibility. What permanent measures are they taking to meet this devastat-

jng situation every these years. The Central Government must come to the aid of the State Governments in 1his matter, in meeting the financial requirements and raising financial resources. It is not correct to say i.hat the present State Government of Andhra Pradesh or any other Government is misusing the funds. It is not correct to say that. Rather, on

he contrary, the Government of Andhra Pradesh is anxious and it has spent all the money *sent* by the Centre only on meeting the drought

ituation. The State Government also has sanctioned crores of rupees to meet the situation. Still the State wants a few crores more and I want to know from the Central Government whether the State Government has ?ent any memorandum regarding the brought situation. If so, what assistance, do they want from the Centre? If the Centre has given some assistance, what more assistance does the State want from the Centre? Has the Central Government sent any team to survey the whole area which iia, been affected by the drought in Andhra Pradesh? If so, what is their estimate of the drought? What, accor-ing to them, is the amount that is needed to meet the drought situation in Andhra Pradesh? To what extent the Centre has provided assistance? Apart from this, I want to know from the Minister what arrangements are the Central Government making to meet the present water shortage in different parts of the country, especially in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. Kerala, in Bihar and other parts of the country including Maharashtra? Of course, at present to meet the water scarcity in Madras, water is taken there in railway wagons. How long will this arrangement continue? There are thousands of villages and lakhs of people living there. There are no railways nor buses in those areas. By what methods are vou going to provide drinking water to those people? What are you doing to meet this situation on a permanent basis?

in various parts of the Country

SHRI ARIF MOHD. KHAN: Hon. Members will appreciate that my Ministry is basically concerned with giving help to the State Governments to meet a particular situation. As a long-term measure, which the hon. Member wants to know, the concept of planned economic growth is tl e answer and the entire Govermental machinery is geared up towards realisation of that goal. However, I may specifically point out some programmes which, have been evolved by the Government to meet the drought which keeps occurring. They are increase in irrigation potential, drought prone area programme, district development programme, command area development programme etc. About Andhra Pradesh, we had received a memorandum on 7-4-1983 and the assistance sought for was Rs. 165.12 crores. The Central team was sent to the State to make an on the spot study and assessment and finally an amount of Rs. 68.76 crores was sanctioned. I think this was the specific question which the hon. Member has raised.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Did you receive an_v other Memorandum.?

SHRI ARIF MOHD. KHAN: It is for the State to spend this money. If they feel that they need more money, they can submit a fresh memorandum and they can ask for more assistance. Shri Kulkarni wantod to know about Maharashtra Government. They asked for Rs. 27.42 crores in their supplementary memorandum. During 1982-83, an amount of Rs. 2,67 crores was sanctioned and for 1983, Sir, I am making the information available to the honourable Member. I have stated again and again that we do not have limitless resources. We have to distribute accordingly.

SHRI A. G. KULKARNI: But the people will die by that time.

255 Calling Attention [RAJYA SABHA] to severe drought

SHRI ARIF MOHD. KHAN: Sir, for 1983-84, a sum of Rs. 2.97 crores was sanctioned and, Sir, as I have stated, in the first memorandum they had asked for assistance only for ten districts and in the supplementary memorandum they identified villages in 21 districts and then this assistance was made available to the Maharashtra Government.

SHRI A. G. KULKARNI: It is only a fleabite, Mr. Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Yes, Mr. Maqsood Ali Khan.

MAQSOOD SHRI ALI KHAN (Karnataka) Sir, Karnataka is also in the grip of serious drought. Sir, our State submitted a memorandum to the Government for providing relief to the drought-affected areas in the State sometime during the first week fo February. And, Sir, the Government of India sent a Central Team to study the conditions in the State from 17th to 23rd | February. I do not know what the recommendations of this Central Team have been. But, so far as the conditions in our State are concerned, out of the twenty districts in Karnataka, I think there is only one district which has not been affected by drought that is the district of Coorg and, all the other districts have been affected to an extent, larger or smaller. About 120 taluks are seriously affected and the villages that have been affected are of the order of about fifteen thousand or more and the conditions are again of the same magnitude as in other States. No drinking water is available in most of the villages; the people are finding it difficult to get food; no fodder is available for the cattle; and there is unemployment of the agricultural labour. The Government of Karnataka is making a request to the An-dhra Pradesh Government to supply rice to that State and I do not know how far their efforts have fructified. But I would request the Central Government to see that rice is supplied fo our state to meet its needs

in various parts of the Country

Sir, the assistance that has been sought by the State is of the order of about Rs. 51 croreg and the State wanted that Rs. 25 crores should at once be released. I do not know how much amount has been released as an *ad hoc* measure. I think the honourable Minister would throw some light on this.

Coming to the other point, Sir, about drinking water and the bore-wells, we wanted assistance of the order of about twenty crores and that has been included in the Rs. 51 crores asked for. I would like to know how much money has been provided for providing drinking water to the villages and the urban areas. As regards the NREP, the State is taking up this scheme and everywhere this scheme is being enforced. We wanted about Rs. 19-20 crores for this programme and if the Central assistance has gone to the State, then the Government of Karnataka would be able to use it and I would request the honourable Minister to throw light on this point also.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: Sir, the total assistance to Karnataka was to the tune of Rs. 8.81 crores during 1982-83 and for expenditure up to the 30th June. 1983, Rs. 13.40 crores for drinking water supply. Then, under the non-Plan ceiling, it is Rs. 10 lakhs for 1982-83 and under the Plan head, it is Rs. 7.46 crores.

SHRI MAQSOOD ALI KHAN: What about this year?

SHRI ARIF MOHD. KHAN: For 1983, for drinking water supply, forty lakhs have been provided under the non-Plan head. And under plan Rs 5 crores 13 lakhs. 3 P.M.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU (Andhra Pradesh): I am coming from a drought affected area. and I want to ask...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Your name is not there.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU: But I had given my name.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): But the list prepared by my predecessor does not include your name. Therefore, I cannot *t* ill you.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU: We are to be at your mercy? It is very unfair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Very well.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU: I have given a Calling Attention motion. I am at nobody's mercy, at the mercy of the Chairman, Deputy Chairman or Vice-Chairman.

श्री कलराज मिश्र : श्रीमन्, मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हं ।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Your party man has already spoken.

श्वी बलराज मिश्व : केन्द्र से एक टीम मेजी गई थी उत्तर प्रदेश के लिये और वहां केन्द्र की टीम ने क्या ग्रघ्ययन किया, उस ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है या नहीं ? उसके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद क्या उस का सुझाव था साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के ग्रंदर भयंकर सूखा पड़ा हुग्रा है उससे संबंधित ग्रनुदान की कोई मांग ये हैयानहीं की है। वह मंत्री जी बतायें तो बहुत कृपा होगी।

श्वी ग्रारिफ मोहम्मद खान: माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश सरकार ढारा सूखा सहायता के संबंध में मांगी गई सहायता के संबंध में पूछा है । उत्तर प्रदेश सरकार से हमें जापन मिला था पिछले साल जुलाई के महीने में लेकिन जब तक केन्द्रीय दल का गठन किया गया निरीक्षण करने के लिये ग्रीर वहां पर जा कर के ग्रध्ययन करने के लिये स्थिति का तब नक उत्तर प्रदेश बा^ह के प्रकोप का शिकार हो चुका था । उत्तर प्रदेश सरकार से हमें सूचना प्राप्त हुई कि उन्होंने चूंकि ग्रपना पहला ज्ञापन इस ग्राधार पर तैयार किया था कि ऐसा उनका विचार था कि यहां सुखे को स्थिति सितम्बर तक

in various parts 25 of the Country

बनी रहेगी तो उससे पहले हमारा दल जाने वाला था वहां पर बाढ़ आ गई । तो उसके बाद हमारा दल वहां गया । उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ सहायता के लिये दूसरा ज्ञापन भेज दिया । बाढ़ झा जाने के कारण हमने उन हे दूसरे जापना पर निर्णय लिया और 68 करोड़रुपये सहायता की धनराणि उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता की करने के लिय दी लकिन चुंकि बाढ़ आ चकी थो और सूखे की स्थिति जिस झाधार पर रिपोर्ट मांगी गई थी वह स्थिति तब खत्म हो गई ची इसलिय हमने सुखे वाले मामले पर उसको स्वीकार करना उचित नहीं समझा ग्रौर प्रदेश सरकार की तरफ से भी ...

श्री कलराज मिश्र : रिपोर्ट की सिफा-रिश क्या थी ? (व्यवधान)

श्री ग्रारिफ मोहम्मद खान : केन्द्रीय दल की संतुति यह थी कि चूंकि ग्रव बाढ़ ग्रा गई है सुखे की स्थिति नहीं रही है । इसलिये हमें इस संबंध में सहायता करने की जरूरत नहीं है बल्कि केवल वाढ़ के संबंध में जो सहायता कार्य करने हैं उनके लिये केन्द्र THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): The House will now take up Special Mentions. Shri Kalraj Mishra. (Interruptions).

श्वी कलराज मिश्र : श्रोमन् में ...

श्री आरिफ म हम्मद खान : मान्यवर, मैं इस में सुधार करना चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश के संबंध में 68 करोड़ 77 लाख रुप्या दिया गया था 1982-83 के लिये उस ेवाद दूसरा मैमोरंडम हम को मिला जिसमें 165 करोड 12 लाख रुपा। प्रदेश की सरकार द्वारा मांगा गया था ...

अर्था शिव चन्द्र झाः विहार का कितना था?

श्री ग्रारिफ मोहम्मद खानः वह मैं इस बक्त नहीं बता सकता। अप्रैल, 1983 में

Disparities in scales of [RAJYA SABHA] of Central Universities 260 259 Pay of non-teaching staff

[अ) श्रारिफ मोहम्मद खान]

दूसरा ज्ञापन मिला कल हो हमारी टीम गई है बहां पर उसका ग्र**अययन करने के लिय और** जल्दी से जल्दीउसके संबंध में निर्णय लिया 1.00 जायेगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): I declare that the discussion is closed now. *{Interruptions*)

श्री राम भगत पासवान (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, बिहार के बारे में मैं कह देना चाहता हुं : बिहार । (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Order please.

श्री राम भगत पासवानः मैं बिहार के संबंध में प्रछना चाहता हं (व्यवधान)

श्वी शिव चन्द्र झाः बिहार के बारे में बताइये ।

श्री जनदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : बिहार सूखे से ग्रफेक्टिड एरिया (भ्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): No please.

श्री कलराज मिश्र ।

श्री राम भगत पासवान । वहाँ सै एक भ्रारब रुपये की सहायता की मांग की गई है, एक लाख टन ग्रनाज की मांग गई है (भ्यवधान) 65 हजार टन दिया गया है (व्यवधान) एक लाख टन झनाज के लिये मांग की गयी थी ... एक अरब रुपये की मांग की गई थी ... (व्ययधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ft. R. MORARKA): No, please. Order please. Please sit down. (Interruptions). You see, the discission is closed. The Minister has ;one away. Now, it is not proper it all for you to defy the Chair and to on making a speech. Kindly be to-operate with the me.

श्री राम भगत पासवान : आपसे परमीशन चाहता हं :

REFERENCE TO THE ALLEGED DISPAR'TIES IN SCALES OF PAY OF NON-TEACHING STAFF OF . CENTRAL UNIVERSITIES

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन, मैं सदन के माध्यम से जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नान टीचिंग स्टाफ हैं उनके ग्रन्दर जो पै डिसपैरिटी है, उस संबंध में ध्यान ग्राकषित करना चाहता हूं। उस वेतन की विषमता को लेकर यनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन ने, यनिवसिटी प्रांटस कमीशन की एक कमैटी बनायी थी, उस कमैटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की ग्रौर उस रिपोर्ट के ग्रन्दर उस कमैटी ने यह दिया कि जो भी वेतन की विषमता है, यह निश्चित रूप से जो गैरणिक्षक कर्मचारी विश्वविद्यालयों के ग्रंदर हें उनको समान करना चाहिए और उनकी पदोन्नति के जो अवसर हैं वे, अवसर भी उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसलिये उसमें सुघार करना चाहिए । इस रिपोर्ट को यु० जी० सी० ने स्वीकार कर लिया ग्रौर स्वीकार करने के पश्चात ग्रब बाकी यनिवरसिंटियों के अन्दर तो यह व्यवस्था है लेकिन बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के अंदर जो बनारस हिन्दू यूनिवसिटी में मैडिकल कालेज है श्रोर उससे संबंधित चिकित्सालय हैं जैसे सर सुदर लाल हास्पिटल, वहां जोकर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को जोवेतनकी विषमता दूर करने के लिये सुविधा उपलब्ध कराने की बात य० जी० सी० ने स्वीकार की थीं, वह उनके ऊपर लागू नहीं की हैं । उस संबंध में सर सुन्दरलाल हास्पिटल एम्पतलाई के मह। मंत्री का एक पत्न ग्राया है उस को में मल रूप से वहा पड़ने का प्रयास कर रहा हं ग्रीर मैं विशयकर शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूगा कि वे इस पर विचार करके यु० जी० सी० के चैयरमैन को निर्देशित करे कि उस हिसाब से उनके वैतन की विषमत